बजट से एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में आएगी तेजी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: गुरुवार को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानमंडल में राज्य का बजट पेश करेगी। अपने नौवें बजट से सरकार एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था की तरफ तेज कदम बढ़ाने की कोशिशें करती दिखेगी। सबसे अधिक जोर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर नजर आएगा। सरकार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। साथ ही नये शहरी क्षेत्रों के विकास और मेट्रो परियोजनाओं का काम तेज करने का इंतजाम इस बजट में कर सकती है।

इस बजट से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की योजना को आगे बढ़ाएगी। इस मद में बड़ी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। ब्लाक स्तर पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना भी है। गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए सरकार नई योजनाएं भी ला सकती है।

राज्य सरकार नये शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए बड़ी धनराशि दे सकती है। पूर्व के बजट में सरकार ने इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये दिए थे। इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों में चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं के कामों को गति देने का इंतजाम भी बजट में नजर आएगा। सरकार बजट से मौजूदा सभी एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ने की योजनाओं के लिए धनराशि जारी करेगी। सभी एक्सप्रेसवे जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक से दूसरे शहर पहुंचने में न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि प्रदेश में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। चार नये एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। प्रदेश सरकार नये औद्योगिक गलियारों के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही इसके लिए बजट आवंटन कर सकती है।

रिहंद-ओबरा में पहला पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भी सरकार बजट आवंटन कर सकती है। प्रदेश में स्थापित होने वाला यह पहला पंप स्टोरेज पावर प्लांट करीब 600 मेगावाट क्षमता का होगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. द्वारा पंप स्टोरेज पावर प्लांट की स्थापना के लिए डीपीआर बनाने का काम एक कंसल्टेंट को सौंपा गया है।

- बिजली उत्पादन को पहले पंप स्टोरेज प्लांट के लिए मिलेगी रकम
- कल पेश होने वाले बजट से प्रदेश के विकास को रफ्तार देगी सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 20 फरवरी को लगातार छठवीं बार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार करीब आठ लाख करोड़ रुपये हो सकता है। बजट में विकास कार्यों के लिए सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया था।